

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: एम०के० सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1078- द. / 14 विरुद्ध आदेश दिनांक 11.2.14 पारित द्वारा
अपर कलेक्टर, कटनी प्रकरण क्रमांक 32 / पुनरीक्षण / अ-६ / 2011- 13

- 1- श्रीमती सुमित्राबाई बेवा स्व. श्री माधवप्रसाद सेन
निवासी ग्राम खन्ना बजारी तह. बरही जिला कटनी म.प्र.
- 2- अजीत कुमार सेन वल्द स्व. श्री माधव प्रसाद सेन
नाबालिग, द्वारा बली मॉ श्रीमती सुमित्राबाई
बेवा स्व. श्री माधव प्रसाद सेन
निवासी ग्राम खन्ना बजारी तह. बरही जिला कटनी म.प्र.
- 3- उज्ज्वल सेन वल्द स्व. श्री माधवप्रसाद सेन
नाबालिग, द्वारा बली मॉ श्रीमती सुमित्राबाई
बेवा स्व. श्री माधव प्रसाद सेन
निवासी ग्राम खन्ना बजारी तह. बरही जिला कटनी म.प्र.
- 4- गायत्री सेन वल्द स्व. श्री माधव प्रसाद सेन
नाबालिग, द्वारा बली मॉ श्रीमती सुमित्राबाई
बेवा स्व. श्री माधव प्रसाद सेन
निवासी ग्राम खन्ना बजारी तह. बरही जिला कटनी म.प्र.

विरुद्ध

परभीबाई बेवा बाबूलाल सेन
निवासी ग्राम खन्नाबजारी तह. बरही
जिला कटनी म.प्र.

श्री एस. के. वाजपेई, अधिवक्ता, आवेदकगण

: आदेश :

(आज दिनांक 20/12/2014 को पारित)

अ-6/12-13 में पारित आदेश दिनांक 1-2-14 के विरुद्ध न.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम चन्ना बजारी निवासी छुटई सेन के दो पुत्र बाबूलाल एवं मुलई थे। बाबूलाल के कोई सान नहीं था। मुलई सेन के दो पुत्र थे। बाबूलाल द्वारा भाई मुलई के छोटे पुत्र माधव के पक्ष में अपनी संपत्ति वसीयत दिनांक 5-11-89 को की गई। वर्ष 2009 में बाबूलाल की मृत्यु होने पर माधव सेन द्वारा संशोधन दर्ज कराने का प्रयास किया गया परंतु हल्का पटवारी द्वारा दर्ज नहीं किया गया। माधव सेन द्वारा वसीयत पेश न करने पर अनावेदक परभी बाई के माध्यम से संशोधन क्रमांक 01 आदेश दिनांक 2-10-09 दर्ज किया गया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 4-5-11 द्वारा स्वीकार की एवं वसीयत के आधार पर नामांतरण किए जाने के आदेश दिए। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदिका न अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जिसमें अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश दिनांक 14-3-14 को पारित करते हुए निगरानी स्वीकार की एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।


3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है। लिखित बहस में यह तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी न प्रकरण में गुणवत्ता पर आदेश पारित किया था जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के न्यायालय में संहिता की धारा 44(25) के तहत होना चाहिए थी। अपीलीय आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण चक्र योग्य नहीं है।

यह तर्क दिया गया है कि अपर कलेक्टर के समान निगरानी चलाने योग्य नहीं है क्योंकि संहिता में हुए संशोधन 31.12.11 के उपरान्त कलेक्टर/अपर कलेक्टर को अपील पर पुनरीक्षण सुनने के अधिकार सम्पन्न कर दिए गए हैं यह अधिकार कबल अपर मंडल को है। अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी 4-5-13 को पेश की गई है। अतः कलेक्टर द्वारा पारित विवादित आदेश शून्य आदेश होने से अपास्त किटन योग्य है। विचाराधिकार संबंधी आपत्ति किसी भी स्तर पर की जा सकती है।

4- अनावेदिका प्रकरण में एकपक्षीय है।

5- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध निगरानी दिनांक 11-6-13 को पेश की गई है और उन्होंने उक्त निगरानी में आलोच्य आदेश दिनांक 1-2-14 को पारित किया गया है। संहिता की धारा 50 में हुए संशोधन दिनांक 30-12-13 के अनुसार कलेक्टर/अपर कलेक्टर को किसी पक्षकार के आवेदन पर पुनरीक्षण सुनने की अधिकारिता समाप्त कर दी गई है। संहिता में हुए संशोधन के प्रकाश में अनावेदिका द्वारा अपर कलेक्टर के सम्क्ष प्रस्तुत की गई पुनरीक्षण को उन्हें सुनने का अधिकार नहीं था अतः अपर कलेक्टर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह क्षेत्राधिकार रहित होकर प्रारंभ से ही शून्य है। दर्शित परिस्थिति में उसे स्थिर नहीं रखा जा सकता। चूंकि अपर कलेक्टर का आदेश इसी बिंदु पर निरस्ती योग्य है अतः आवेदक की ओर से उठाये गये अद्य बिंदुओं पर विचार आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार एवं अधिकारिता के बाहर होने के कारण निरस्त किया जाता है।


(एम. के. सिंह)

अपर
ज.स. मण्डल मध्यप्रदेश,
सर्गभयूर